

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड और अन्य

बनाम

साधु राम

(2008 की सिविल अपील संख्या 2549)

8 मार्च, 2008

(तरुण चटर्जी और हरजीत सिंह बेदी, जे.जे.)

पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961; धारा.18/ भारत का संविधान, 1950; अनुच्छेद 226:

भूखंडों की नीलामी - प्राधिकरण द्वारा दूसरी नीलामी का आदेश रद्द करना - दूसरी नीलामी में आरक्षित मूल्य का खुलासा न करने के आधार पर चुनौती - उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति - सही - माना गया: गलत मुख्य प्रशासक, अंतिम प्राधिकारी ने नीलामी बोलियों को मंजूरी नहीं दी पहली नीलामी- नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को नीलामी अपने पक्ष में समाप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था - दूसरी नीलामी का आदेश प्राधिकरण द्वारा दिया गया था क्योंकि पहले की नीलामी में अपेक्षित राशि नहीं मिल सकी थी, इसके अलावा, मामले के तथ्यों और

परिस्थितियों में, भूखंडों की दूसरी नीलामी का निर्देश देने वाले मुख्य प्रशासक की कार्रवाई निष्पक्ष थी और मनमानी नहीं थी और शक्ति का रंगीन प्रयोग नहीं था - हालांकि आरक्षित मूल्य उत्तरदाताओं को ज्ञात नहीं था, लेकिन यह उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए पहली नीलामी में उच्चतम बोली लगाने वाले को वैकल्पिक भूखंडों के आवंटन का निर्देश देने की अनुमति नहीं दे सकता था - न्यायिक समीक्षा का दायरा।

खुली नीलामी में वाणिज्यिक भूखंडों, अर्थात् दुकान भूखंडों और बूथ भूखंडों के आवंटन के संबंध में, अपीलकर्ता संख्या 2 द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी। उत्तरदाताओं को भूखंडों के लिए सबसे अधिक बोली लगाने वाला घोषित किया गया था, और उन्होंने बोली राशि की आवश्यक राशि जमा की। बाद में मुख्य प्रशासक ने एक भूखंड और तीन बूथों के संबंध में दी गई बोलियों के लिए अपनी मंजूरी दे दी और अन्य सभी भूखंडों के संबंध में आयोजित नीलामी को अस्वीकार कर दिया। अन्य सभी भूखंडों के संबंध में आयोजित नीलामी हेतु निर्देशित किया गया।

उत्तरदाताओं द्वारा जमा की गई राशि वापस करने और शेष भूखंडों के संबंध में द्वितीय नीलामी का आदेश देना। तदनुसार, दूसरी नीलामी हुई। उत्तरदाता ने रिट याचिका दायर कर मुख्य प्रशासक के आदेश को

चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी वैकल्पिक भूखंड आवंटित करने के हकदार थे। इसलिए वर्तमान अपील करता है।

अपीलार्थी-अधिकारियों ने प्रस्तुत किया कि उत्तरदाताओं के पक्ष में नीलामी की घोषणा बोर्ड के मुख्य प्रशासक की अंतिम मंजूरी के अधीन थी और क्योंकि मुख्य प्रशासक ने उनके पक्ष में नीलामी को खारिज कर दिया था, अपीलकर्ताओं की कार्यवाही ने दूसरी नीलामी का निर्देश दिया। प्रश्नगत सम्पत्ति पर अपीलकर्ताओं द्वारा सम्पत्ति की दूसरी नीलामी का निर्देश देना पूरी तरह से उचित था। विचाराधीन संपत्तियाँ पूरी तरह से उचित थीं; उत्तरदाताओं द्वारा दी गई बोलियाँ आरक्षित मूल्य से कम थी, जिसके परिणामस्वरूप मुख्य प्रशासक द्वारा बोलियों को अस्वीकार कर दिया गया, जिनके पास अधिनियम की धारा 18 के तहत बिना कोई कारण बताए बोलियों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का विशेषाधिकार था; बाद की नीलामी में, उन्हीं भूखंडों के संबंध में अधिक कीमत प्राप्त की गई; उच्च न्यायालय द्वारा आरक्षित मूल्य के गैर-प्रकटीकरण के आधार पर अपीलकर्ताओं की कार्यवाही को अमान्य करना उचित नहीं था और भले ही नीलामी के समय आरक्षित मूल्य का गैर-प्रकटीकरण को अनियमितता/अवैधता माना जाए। उच्च न्यायालय अधिक से अधिक पूरी नीलामी को रद्द कर सकता है लेकिन प्रतिवादियों के पक्ष में नीलामी की पुष्टि नहीं कर सकता; और वास्तव में, उत्तरदाताओं को बोली राशि के

लिए उनके द्वारा जमा की गई राशि पहले ही वापस मिल चुकी थी और इसलिए, उनके पास अपने दावे के लिए कोई निर्वाह अधिकार नहीं था।

उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत किया कि चूंकि आरक्षित मूल्य का खुलासा सार्वजनिक सूचना में या नीलामी के समय इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों को नहीं किया गया था, नीलामी में उत्तरदाताओं द्वारा किए गए प्रस्तावों को मुख्य प्रशासक द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता था इसलिए बोर्ड की ओर से इस अस्वीकृति को अनुचित, अतार्किक और अवैध माना जाना चाहिए; और यह कि उत्तरदाताओं को सूचित नहीं किया गया था

17 दिसंबर, 2004 के पत्र में भी उनकी बोलियों को अस्वीकार करने का कारण बताया गया है और कहा गया है कि उनके द्वारा पेश की गई बोलियों को अपीलकर्ताओं ने 6 महीने के बाद सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना खारिज कर दिया था।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए

अभिनिर्धारित : 1. यह सच है कि आरक्षित मूल्य न तो उत्तरदाताओं को पता था और न ही उत्तरदाताओं को भूखंड आवंटित करने के उद्देश्य से इसका विज्ञापन दिया गया था, लेकिन यह उच्च न्यायालय को उत्तरदाताओं को वैकल्पिक भूखंड आवंटित करने का निर्देश देने की अनुमति नहीं दे सकता था। (पैरा - 9) [53-सी, डी]

2.1 पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम की धारा 18 के तहत प्रावधानों के संदर्भ में, यदि बोर्ड का मुख्य प्रशासक नीलामी को अस्वीकार करता है, तो उसे ऐसी अस्वीकृति के लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसी अस्वीकृति की जाती है, तो धारा 18 में केवल यह प्रावधान है कि बोली लगाने वाले द्वारा जमा की गई राशि बोर्ड की मार्केट कमेटी द्वारा बिना ब्याज के वापस की जानी चाहिए। इस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि चूंकि बोर्ड के मुख्य प्रशासक नीलामी बोलियों को मंजूरी देने के लिए अंतिम प्राधिकारी थे, जो उनके अपने विवेक से मंजूरी नहीं किए गए थे, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता था क्योंकि आरक्षित मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया सार्वजनिक सूचना में और प्रतिवादियों को इसकी जानकारी नहीं थी, उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए वैकल्पिक भूखंडों के आवंटन का निर्देश दे सकता था। (पैरा - 11) [54-ए, बी, सी]

2.2 राजस्थान आवास बोर्ड एवं अन्य बनाम जे.एस. निवेश और अन्य, के निर्णित मामले में, इस न्यायालय ने शक्ति की रूपरेखा पर विचार किया जो उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर एक रिट याचिका में प्रयोग करेगा जब चुनौती एक सार्वजनिक निकाय द्वारा आयोजित नीलामी को रद्द करने की थी जहां मुख्य विचार निष्पक्षता

और सार्वजनिक राजस्व का सृजन और यह माना गया कि भले ही अंतिम निर्णय में कुछ दोष पाया गया जिसके परिणामस्वरूप नीलामी रद्द कर दी गई।

नीलामी में, न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग बहुत ध्यान और सावधानी से करना चाहिए और इसका प्रयोग केवल सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाने में करना चाहिए। उस निर्णय में यह भी माना गया था कि जब आवास बोर्ड के अध्यक्ष के पास बोली स्वीकार करने के संबंध में अंतिम अधिकार होता है, तो नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले व्यक्ति को तब तक नीलामी अपने पक्ष में संपन्न कराने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता जब तक सभापति ने इस आशय का आदेश पारित नहीं करता। (पैरा-11) [55-बी, सी, डी, ई]

टाटा सेल्यूलर बनाम यू. ओ. आई. (1994) 6 एस. सी. सी. 651
और राजस्थान आवास बोर्ड एवं अन्य बनाम जे.एस. निवेश और अन्य
(2007) 1 एस. सी. सी. 477- पर निर्भर।

3.1 मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, बोर्ड के मुख्य प्रशासक की कार्रवाई उचित थी और रद्द करना मनमाना नहीं था। दूसरी नीलामी विचाराधीन भूखंडों के संबंध में आयोजित की गई थी और उक्त नीलामी से, हालांकि आरक्षित मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया था,

अपीलार्थियों को बहुत उंचे प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इसके अलावा, उत्तरदाताओं द्वारा अपीलार्थियों के पास जमा की गई राशि उत्तरदाताओं को प्राप्तकर्ता चेक के माध्यम से वापस कर दी गई थी, जिसे उनके द्वारा विधिवत भुनाया गया था। ऐसी स्थिति होने के कारण, यह न्यायालय उत्तरदाताओं के प्रस्तावों को अस्वीकार करने में बोर्ड के मुख्य प्रशासक की ओर से कोई दुर्भावना, अनुचितता या मनमानेपन को नहीं पाता है और न ही इसे शक्ति का रंगीन प्रयोग मानते हैं। (पैरा - 12) [56-ए, बी, सी, डी]

3.2 यह रिकॉर्ड में है कि पहली नीलामी में उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए प्रस्ताव उक्त भूखंडों से अपेक्षित राशि प्राप्त नहीं कर सके और यही कारण है कि अपीलकर्ताओं द्वारा बाद की नीलामी के लिए एक नया सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था। दूसरी नीलामी आयोजित की गई और उक्त नीलामी से प्राप्त कीमत उत्तरदाताओं द्वारा की गई पेशकश से कहीं अधिक थी। यह स्थिति होने और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि बाद में नीलामी आयोजित की गई और समाप्त हुई, यह उच्च न्यायालय के लिए खुला नहीं है कि पूर्व में हुई नीलामी को वैध मानते हुए प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तावित दर पर वैकल्पिक भूखंडों के आवंटन का निर्देश दे। (पैरा - 12) [56-ई, एफ, जी, एच]

राजस्थान आवास बोर्ड एवं अन्य बनाम जे.एस. निवेश और अन्य

(2007) 1 एससीसी 477- पर निर्भर।

3.3 अगर यह मान भी लिया जाए कि आरक्षित मूल्य सार्वजनिक सूचना में दिया जाना था, तब भी उच्च न्यायालय के लिए सबसे अच्छा रास्ता वैकल्पिक भूखंडों के आवंटन का निर्देश देकर अपनी राय को प्रतिस्थापित करने के बजाय पूरी नीलामी को रद्द करना होगा। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को स्वीकार करना मुश्किल है चूंकि आरक्षित मूल्य उत्तरदाताओं को ज्ञात नहीं था और वे उक्त नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाने वाले पाए गए, इसलिए उन्होंने वैकल्पिक भूखंडों का आवंटन प्राप्त करने का अधिकार हासिल कर लिया है और अपीलकर्ताओं के पास उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए उच्चतम प्रस्तावों को अस्वीकार करने या नीलामी को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं था। चूंकि पूरी नीलामी रद्द कर दी गई थी, तो उच्च न्यायालय उसी नियम और शर्तों पर वैकल्पिक भूखंडों के आवंटन का आदेश कैसे पारित कर सकता था, जबकि रद्द करने के बाद, दूसरी नीलामी आयोजित की गई थी, जिसकी कीमत द्वारा दिए गए प्रस्ताव की तुलना में बहुत अधिक थी। उत्तरदाताओं. (पैरा - 14) [57-सी, डी, ई, एफ]

3.4 आरक्षित मूल्य का खुलासा न करने में कुछ भी अनुचित नहीं पाया गया है। यह आम जानकारी है कि जब आरक्षित मूल्य का खुलासा

किया जाता है, तो बोली लगाने वाले अक्सर गुट बनाते हैं और घोषित मूल्य पर या उसके आसपास बोली लगाते हैं, जबकि बाजार मूल्य बहुत अधिक होता है। इसलिए, यह न्यायालय उच्च न्यायालय से सहमत नहीं है कि अपीलकर्ताओं ने निविदाएं आमंत्रित करते समय या यहां तक कि नीलामी आयोजित करते समय आरक्षित मूल्य का खुलासा न करके अनुचित तरीके से काम किया था। (पैरा-14) [57-एफ, जी; 58-ए]

3.5 यह उच्च न्यायालय के लिए खुला नहीं था कि वह अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए अपीलकर्ताओं को निर्देश दे कि उत्तरदाताओं को वैकल्पिक भूखंडों का आवंटन करने के लिए पहली आयोजित की गई नीलामी को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि बोर्ड के मुख्य प्रशासक द्वारा बिना कोई कारण बताए और इस आधार पर भी कि अपीलकर्ताओं द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस में आरक्षित मूल्य का खुलासा नहीं किया गया था। (पैरा - 15) [58-बी, सी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2549/2008।

2005 की सिविल रिट याचिका संख्या 816 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 27.04.2006 से,

के साथ

सिविल अपील संख्या 2550-2557/2008

अपीलकर्ताओं की ओर से नीरज कुमार जैन, भरत सिंह, संजय, संदीप चतुर्वेदी, उमंग शंकर और उग्र शंकर प्रसाद।

उत्तरदाता की ओर से पी. एस. पटवालिया, ए. पी. भंडारी, एस. सी. पटेल, तेजस पटेल, सुभाष भोमिक, संजीव के. पब्बी, शिखा रॉय, एस.के. सभरवाल, जे. एस. पुरी, यशपाल ढींगरा और सेंथिल जगदीसन।

न्यायालय का निर्णय **तरूण चटर्जी, जे.** द्वारा सुनाया गया। 1. छुट्टी स्वीकृत।

2. अपीलों का ये समूह में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के 27 अप्रैल, 2006 के एक सामान्य निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुआ है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर, 2004 के आदेश को चुनौती देने वाले उत्तरदाताओं द्वारा दायर की गई रिट याचिकाओं के एक समूह को अनुमति दी थी जिसमें खुली नीलामी में उनके पक्ष में भूखंडों का आवंटन रद्द कर दिया गया। चूंकि इन अपीलों के निपटान में कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्न उठते हैं और उच्च न्यायालय ने **मंगत राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य** [2005 की सी. डब्ल्यू.

पी. संख्या 213 पर 27 अप्रैल, 2006 को निर्णय लिया गया] में पारित फैसले के अनुसरण के बाद रिट याचिकाओं के पूरे समूह का निपटारा कर दिया है, हम 27 अप्रैल, 2006 के फैसले से इन अपीलों को दाखिल करने के लिए अग्रणी तथ्यों को लेते हैं। अप्रैल, 2006 पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के 2005 के सीडब्ल्यूपी संख्या 213 में पारित हुआ, जो इस प्रकार हैं:-

3. अपीलकर्ता पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961 (संक्षेप में "अधिनियम") ए के तहत वैधानिक प्राधिकारी हैं। मार्केट कमेटी, पंचकुला, हरियाणा के कार्यालय, अपीलकर्ता नंबर 2 द्वारा एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था जिसमें व्यापारियों और आम जनता को नई अनाज और सब्जी मंडी पंचकुला में 8 जुलाई, 2004 को होने वाली खुली नीलामी में वाणिज्यिक स्थलों को खरीदने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस नीलामी के द्वारा दुकान के प्लॉट (62 नग) और 20'X50' आकार के बूथ प्लॉट की नीलामी की जानी थी। 16 मई, 2003 को एक कार्यालय आदेश द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने सिफारिश की कि 20'X50' मापने वाले भूखंड के लिए आरक्षित मूल्य 33,91,391/- रुपये निर्धारित किया जाए जिसको बोर्ड के मुख्य प्रशासक के स्तर पर स्वीकृती दे दी गई। हालाँकि, इस प्रकार निर्धारित आरक्षित मूल्य का उल्लेख न तो सार्वजनिक सूचना में किया गया था और न ही नीलामी शुरू होने से पहले इसकी

घोषणा की गई थी। भूखंडों की नीलामी तय कार्यक्रम के अनुसार हुई। उत्तरदाताओं को भूखंडों के लिए उच्चतम बोली लगाने वाला घोषित किया गया जिन्होंने कानून की आवश्यकता के अनुसार बोली राशि का 25% जमा किया। 24 जुलाई, 2004 को, 8 जुलाई, 2004 को आयोजित उपरोक्त नीलामी की नीलामी समिति की रिपोर्ट मार्केट कमेटी, पंचकुला के समक्ष रखी गई, जिसने 24 जुलाई, 2004 के एक प्रस्ताव द्वारा नीलामी बोलियों की पुष्टि की सिफारिश की और निर्णय लिया गया कि अधिनियम की धारा 18 के तहत मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की मंजूरी ली जाएगी। 30 नवंबर, 2004 को मुख्य प्रशासक की ओर से कार्यकारी अधिकारी-सह-सचिव, मार्केट कमेटी, पंचकुला को एक पत्र भेजा गया था जिसके द्वारा कुछ विसंगतियों से अवगत कराया गया था। 6 दिसंबर, 2004 को कार्यकारी अधिकारी ने मुख्य प्रशासक को एक पत्र लिखकर सूचित किया कि बताई गई विसंगतियों पर ध्यान दिया गया है और अनुमोदन के लिए अनुरोध किया गया है। 15 दिसंबर, 2004 को मुख्य प्रशासक ने 20'X50' मापने वाले प्लॉट नंबर 1 और 12'X27 मापने वाले नंबर 149, 150, 152 वाले तीन बूथों के लिए दी गई बोलियों के संबंध में अपनी मंजूरी दे दी। अन्य सभी भूखंडों की नीलामी रद्द कर दी गई और यह आदेशित किया गया कि उत्तरदाताओं को राशि लाँटाई जाए और भूखंडों को 20 दिसंबर, 2004 को खुली नीलामी में रखा जाए। 17 दिसंबर, 2004

को, उत्तरदाताओं को बाजार समिति से एक संचार प्राप्त हुआ कि चूंकि उनके पक्ष में नीलामी को मुख्य प्रशासक द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था उनके द्वारा जमा की गई बोली राशि का 25 प्रतिशत वापस किया जा रहा है। दूसरी सार्वजनिक नीलामी, जैसा कि तय कार्यक्रम के अनुसार, 20 दिसंबर, 2004 को आयोजित की गई थी, और नीलामी खरीदारों से पिछली कीमत से अधिक कीमत प्राप्त की गई थी।

4. 4 जनवरी, 2005 को उत्तरदाताओं ने उनके पक्ष में भूखंडों के आवंटन को रद्द करने के 17 दिसंबर, 2004 के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए रिट याचिकाओं का समूह दायर किया। उच्च न्यायालय के समक्ष उत्तरदाताओं द्वारा दायर की गई रिट याचिकाओं के बैच को सुनवाई के लिए लिया गया और जो मुख्य निर्णय पारित किया गया वह **मंगत राम और अन्य** बनाम **हरियाणा राज्य एवं अन्य** के मामले में, 2005 के सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 213 पर 27 अप्रैल, 2006 को निर्णय लिया गया और उसके बाद, उसी निर्णय के अनुसरण में ही शेष सभी रिट याचिकाओं का निपटारा यह कहते हुए किया गया कि उत्तरदाता वैकल्पिक भूखंड आवंटित करने के हकदार थे। उच्च न्यायालय के इन निर्णयों के विरुद्ध अब उत्तरदाताओं द्वारा अलग-अलग अपीलें दायर की गई हैं, जिनके संबंध में पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं के समूह पर निर्णय लेते समय, 2005

के सी. डब्ल्यू. पी. नंबर 213 वाली रिट याचिकाओं में से एक के तथ्यों को इस आधार पर ध्यान में रखा था कि रिट याचिकाओं में कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्न शामिल थे। यह उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया रुख है, इसलिए, हम भी, इस स्तर पर 2005 के सीडब्ल्यूपी संख्या 213 में उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को देखते हैं, जो इस प्रकार हैं: -

(i) नीलामी खरीददारों को आरक्षित मूल्य का खुलासा न करने को ध्यान में रखते हुए, उनके पक्ष में नीलामी की कार्यवाही को न तो रद्द किया जा सकता है और न ही इस आधार पर अनुमोदन से इनकार किया जा सकता है कि उनके द्वारा प्रस्तावित बोली मूल्य आरक्षित मूल्य से कम था;

(ii) आरक्षित मूल्य का गैर-प्रकटीकरण एक अनुचित अभ्यास हुआ।

(iii) उच्चतम बोली लगाने वालों के पक्ष में नीलामी मुख्य प्रशासक द्वारा अंतिम अनुमोदन के अधीन थी, लेकिन अनुमोदन को केवल उन कारणों से अस्वीकार किया जा सकता था जो प्रासंगिक थे और नीलामी क्रेताओं की उच्चतम बोलियों को अस्वीकार करने को उचित ठहरा सकते थे, लेकिन यह मनमाना या निरपेक्ष नहीं हो सकता।

(iv) 17 दिसंबर, 2004 का आदेश रद्द कर दिया जाएगा लेकिन मुख्य प्रशासक नीलामी के नियमों और शर्तों के अनुपालन में अपनी

शक्तियों का प्रयोग करने के लिए खुला होगा ताकि कानून के अनुसार नीलामी की मंजूरी के सवाल पर विचार किया जा सके।

(v) नीलामी खरीददारों द्वारा केवल चेक भुनाने, राशि वापस करने को उनके खिलाफ तथ्य नहीं माना जा सकता है।

5. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उत्तरदाताओं के पक्ष में नीलामी बोर्ड के मुख्य प्रशासक की अंतिम मंजूरी के अधीन थी और चूंकि मुख्य प्रशासक ने उनके पक्ष में उक्त नीलामी को खारिज कर दिया था, इसलिए अपीलकर्ताओं की कार्यवाही पूरी तरह से न्यायोचित थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि उत्तरदाताओं द्वारा दी गई बोलियां आरक्षित मूल्य से कम थी, जिसके परिणामस्वरूप मुख्य प्रशासक ने बोलियों को अस्वीकार कर दिया, जिनके पास अधिनियम की धारा 18 के तहत बिना कोई कारण बताए बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का विशेषाधिकार था। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने हमारे समक्ष यह भी प्रस्तुत किया कि 20 दिसंबर, 2004 को आयोजित बाद की नीलामी में, उन्हीं भूखंडों के संबंध में अधिक कीमत प्राप्त की गई थी। उन्होंने तदनुसार तर्क दिया कि आरक्षित मूल्य का खुलासा न करने के आधार पर अपीलकर्ताओं की कार्यवाही को अमान्य करना उच्च न्यायालय के लिए उचित नहीं था और भले ही नीलामी के समय आरक्षित मूल्य का खुलासा

न करने को अवैध माना जाए। अनियमितता या अवैधता के मामले में, उच्च न्यायालय अधिक से अधिक पूरी नीलामी को रद्द कर सकता है, लेकिन प्रतिवादियों के पक्ष में नीलामी की पुष्टि नहीं कर सका और वास्तव में, उत्तरदाताओं ने पहले ही बाजार समिति से चेक पहले ही वापस प्राप्त कर लिए थे और उन्हें भुना लिया था, इसलिए उनके पास कुछ भी नहीं था उनके दावे को सही ठहराते हुए जीवित रहना।

6. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील की इन दलीलों का उत्तरदाताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने जोरदार विरोध किया। उत्तरदाताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पटवालिया ने तर्क दिया कि चूंकि आरक्षित मूल्य का खुलासा सार्वजनिक सूचना में या नीलामी के समय इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों को नहीं किया गया था, इसलिए नीलामी में उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए प्रस्ताव आयोजित नहीं किए गए। 8 जुलाई, 2004 को बोर्ड के मुख्य प्रशासक द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता था क्योंकि इस तरह की अस्वीकृति को अनुचित, अतार्किक और अवैध माना जाएगा। प्रतिवादियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पटवालिया ने आगे कहा कि उत्तरदाताओं को 17 दिसंबर, 2004 के पत्र में भी उनकी बोलियों को अस्वीकार करने का कारण नहीं बताया गया था और उनके द्वारा पेश की गई बोलियों को 6 महीने के बाद अपीलकर्ताओं द्वारा उन्हें सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना खारिज कर दिया गया था। ।

7. हमने पक्षों के विद्वान वकील की उपरोक्त दलीलों की जांच की है। हमने रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय के फैसले की भी जांच की है और कहा है कि चूंकि नीलामी से पहले आरक्षित मूल्य का खुलासा नहीं किया गया था, जो अनिवार्य था, और उत्तरदाता ऐसे आरक्षित मूल्य को जाने बिना नीलामी में भाग लेने के लिए आगे बढ़े, यह नहीं कहा जा सकता था कि चूंकि उत्तरदाताओं का प्रस्ताव आरक्षित मूल्य से कम था, इसलिए इसे अस्वीकार किया जा सकता था। पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले और 17 दिसंबर, 2004 के आदेश और 8 जुलाई, 2004 को आयोजित नीलामी के नियमों और शर्तों सहित रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सामग्रियों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद, हमारा विचार है कि यह अपील आगे बताए गए कारणों से सफल होनी चाहिए।

8. इससे पहले कि हम पुनरावृत्ति के जोखिम पर पार्टियों की ओर से किए गए अनुरोधों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ें, हम इसे रिकॉर्ड पर रख सकते हैं कि यह विवाद में नहीं है कि प्रश्नगत भूखंडों की नीलामी आयोजित करने के लिए आरक्षित मूल्य न तो दिखाया गया था अपीलकर्ताओं की सार्वजनिक सूचना में और न ही उत्तरदाताओं को इसकी जानकारी थी। यह भी एक स्वीकृत स्थिति है कि उत्तरदाताओं द्वारा जमा किया गया पैसा अपीलकर्ताओं द्वारा जमा किया गया पैसा प्राप्तकर्ता चेक

द्वारा वापस कर दिया गया था, जिसे उत्तरदाताओं द्वारा विधिवत भुनाया गया था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय ने व्यावहारिक रूप से रिट याचिका को इस निष्कर्ष पर अनुमति दी थी कि चूंकि आरक्षित मूल्य सार्वजनिक सूचना में नहीं दिखाया गया था, इसलिए अधिकारियों के पास इस आधार पर प्रतिवादियों के पक्ष में नीलामी रद्द करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था कि उनकी पेशकश आरक्षित मूल्य से कम थे और इसलिए बोर्ड के मुख्य प्रशासक के आदेश से 8 जुलाई, 2004 को आयोजित नीलामी रद्द नहीं की जा सकी।

9. हम उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में व्यक्त इस दृष्टिकोण से सहमत होने में असमर्थ हैं। यह सच है कि आरक्षित मूल्य न तो उत्तरदाताओं को ज्ञात था और न ही उत्तरदाताओं को भूखंड आवंटित करने के उद्देश्य से इसका विज्ञापन किया गया था, लेकिन हमारे विचार में, यह उच्च न्यायालय को उत्तरदाताओं को वैकल्पिक भूखंडों के आवंटन का निर्देश देने की अनुमति नहीं दे सकता है। यह मानते हुए भी कि सार्वजनिक सूचना में आरक्षित मूल्य का उल्लेख न करने में अधिकारियों की ओर से त्रुटि हुई थी, तब भी, उच्च न्यायालय के लिए प्रतिवादियों को 8 जुलाई, 2004 को आयोजित नीलामी के आधार पर वैकल्पिक भूखंडों के आवंटन का निर्देश देना उचित नहीं था।

10. यह भी विवाद में नहीं है कि नीलामी बोलियों को मंजूरी देने का अंतिम प्राधिकारी बोर्ड का मुख्य प्रशासक था। आगे बढ़ने से पहले, हम अधिनियम की धारा 18 का उल्लेख कर सकते हैं जो निम्नानुसार है: -

"अधिनियम की धारा 18 के तहत भूखंडों की सभी बिक्री चाहे ड्रा की खुली नीलामी द्वारा, बोर्ड के सीए द्वारा अनुमोदन के अधीन हैं। हालाँकि, वह बिना कोई कारण बताए ऐसी मंजूरी की सहमति दे भी सकता है और नहीं भी। प्रस्ताव अस्वीकार होने की स्थिति में, कुल कीमत का 1/4 भाग के रूप में जमा की गई राशि एम.सी. द्वारा बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।" (जोर दिया गया)

11. जैसा कि यहां ऊपर उद्धृत किया गया है, अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि नीलामी बोर्ड के मुख्य प्रशासक द्वारा अनुमोदित होने के बाद ही अंतिम होगी। यदि बोर्ड का मुख्य प्रशासक नीलामी को अस्वीकार कर देता है, तो उसे ऐसी अस्वीकृति के लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि ऐसी अस्वीकृति की जाती है, तो धारा 18 में केवल यह प्रावधान है कि बोली लगाने वाले द्वारा जमा की गई राशि बोर्ड की मार्केट कमेटी द्वारा बिना ब्याज के वापस की जानी चाहिए। इस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि चूंकि बोर्ड के मुख्य प्रशासक नीलामी बोलियों को मंजूरी

देने के लिए अंतिम प्राधिकारी थे, जिन्हें अपने विवेक से मंजूरी नहीं दी गई थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता था क्योंकि आरक्षित मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया था सार्वजनिक सूचना में और प्रतिवादियों को इसकी जानकारी नहीं थी, उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए वैकल्पिक भूखंडों के आवंटन का निर्देश दे सकता था। सरकारी अनुबंधों और राज्य सरकार द्वारा भूखंडों की नीलामी सहित संविदात्मक मामलों में अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा/हस्तक्षेप के दायरे को इस न्यायालय द्वारा निर्णयों की श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निपटाया गया है। **टाटा सेल्यूलर बनाम भारत संघ** [1994 (6) एस. सी. सी. 651], निर्णयों की न्यायिक समीक्षा में जिस सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए, विशेष रूप से निविदा की स्वीकृति और अनुबंध के पुरस्कार से संबंधित, उस पर विस्तार से विचार किया गया और यह माना गया कि न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत सरकारी निकायों द्वारा संविदात्मक शक्तियों को मनमानी या पक्षपात को रोकने के लिए लागू होगा। लेकिन यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में अंतर्निहित सीमाएँ हैं। उस निर्णय में यह माना गया कि न्यूनतम या किसी भी निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार भी सरकार को उपलब्ध है, लेकिन किसी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करते समय संविधान के अनुच्छेद 14 में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखा

जाना चाहिए। यदि सरकार सर्वोत्तम कोटेशन प्राप्त करने का प्रयास करती है तो अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का कोई प्रश्न नहीं हो सकता है और साथ ही सर्वोत्तम कोटेशन को रद्द करने का भी कोई प्रश्न नहीं हो सकता है यदि उसे लगता है कि सर्वोत्तम कोटेशन भी बेहतर बाजार प्रश्नगत भूखंडों की कीमत पाने के लिए सरकार की संतुष्टि के अनुरूप नहीं है। इसलिए उस निर्णय में यह माना गया कि राज्य सरकार और उसकी संस्थाओं को यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने मनमानी शक्ति का प्रयोग किया है जब उन्हें पता चला कि उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए सर्वोत्तम प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि विचाराधीन भूखंडों का बाजार मूल्य उत्तरदाताओं द्वारा दी गई राशि से बेहतर होगा। उस निर्णय में आगे यह कहा गया कि चूंकि न्यायिक समीक्षा की शक्ति निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं है, इसलिए न्यायालय अपने निर्णय को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। वर्तमान मामले में, यह विवाद में नहीं है कि अपीलकर्ताओं द्वारा नीलाम किए गए भूखंड राज्य सरकार के साधनों से संबंधित थे, जिनसे राज्य के वित्तीय हितों की रक्षा की उम्मीद की जानी चाहिए। **राजस्थान आवास बोर्ड और अन्य बनाम जे.एस. निवेश और अन्य** [2007(1) एससीसी 477] में रिपोर्ट किए गए निर्णय में इस न्यायालय ने **टाटा सेल्युलर बनाम भारत संघ** [उपर] के निर्णय सहित इस न्यायालय के पहले के निर्णयों पर गहनता से विचार करने के बाद उस शक्ति की रूपरेखा पर विचार किया जिसे उच्च

न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर एक रिट याचिका में प्रयोग करेगा जब चुनौती एक सार्वजनिक निकाय द्वारा आयोजित नीलामी को रद्द करने की थी जहां मुख्य विचार निष्पक्षता और पीढ़ी थी सार्वजनिक राजस्व का और माना गया कि भले ही अंतिम निर्णय में कुछ दोष पाया गया जिसके परिणामस्वरूप नीलामी रद्द कर दी गई, अदालत को अनुच्छेद 226 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्ति का उपयोग बहुत ध्यान और सावधानी से करना चाहिए और इसका उपयोग केवल सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाने में करना चाहिए। उस निर्णय में यह भी कहा गया था कि जब आवास बोर्ड के अध्यक्ष के पास बोली स्वीकार करने के संबंध में अंतिम अधिकार होता है, तो नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले व्यक्ति को तब तक नीलामी अपने पक्ष में संपन्न कराने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है जब तक कि सभापति ने इस आशय का आदेश पारित नहीं करता।

12. इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, आइए हम इस पर विचार करें कि क्या सार्वजनिक सूचना में आरक्षित मूल्य का खुलासा न करना एक ऐसा आधार है जिस पर उच्च न्यायालय अधिकारियों को विकल्प आवंटित करने का निर्देश दे सकता है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तरदाताओं के पक्ष में साजिश रचता है। पुनरावृत्ति के जोखिम पर, हम ध्यान दे सकते हैं कि सार्वजनिक सूचना में एक शर्त यह थी कि

नीलामी में सर्वोत्तम प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अंतिम अधिकार बोर्ड के मुख्य प्रशासक का था। यह सत्य है कि बोर्ड के मुख्य प्रशासक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। बिना कोई कारण बताए प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया लेकिन अधिनियम की धारा 18 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि बिना कोई कारण बताए ऐसी अस्वीकृति की जा सकती है। आइए अब विचार करें कि क्या बोर्ड के मुख्य प्रशासक की ओर से नीलामी रद्द करने की कार्रवाई अनुचित, मनमानी और अमान्य थी। हमारे विचार में, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, बोर्ड के मुख्य प्रशासक की कार्यवाही निष्पक्ष थी और रद्दीकरण मनमाना नहीं था। दूसरी नीलामी 20 दिसंबर, 2004 को प्रश्नगत भूखंडों के संबंध में आयोजित की गई थी और उक्त नीलामी से, हालांकि आरक्षित मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया था, अपीलकर्ताओं को बहुत ऊंचे प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इसके अलावा, हमें इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखना चाहिए कि उत्तरदाताओं द्वारा अपीलकर्ताओं के पास जमा की गई राशि उत्तरदाताओं को खाता प्राप्तकर्ता चेक के माध्यम से वापस कर दी गई थी, जिसे उनके द्वारा विधिवत भुनाया गया था। ऐसी स्थिति होने पर, हम उत्तरदाताओं के प्रस्तावों को अस्वीकार करने में बोर्ड के मुख्य प्रशासक की ओर से न तो कोई दुर्भावना, अनुचितता या मनमानी पाते हैं और न ही हम इसे शक्ति का रंगीन प्रयोग पाते हैं। इसके अलावा, **राजस्थान आवास बोर्ड और अन्य**

बनाम जी. एस. निवेश और अन्य [उपर] में इस अदालत के फैसले के मद्देनजर, चूंकि बोलियों को मंजूरी देने का अंतिम अधिकार मुख्य प्रशासक के पास था, इसलिए यह स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति ने नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाई थी, उसे नीलामी समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं मिला। जब तक मुख्य प्रशासक इस आशय का आदेश पारित नहीं कर देता तब तक पक्ष रखें और नीलामी की कार्यवाही हमेशा रद्द की जा सकती है। यह रिकॉर्ड में है कि उत्तरदाताओं ने 8 जुलाई, 2004 की नीलामी में जो पेशकश की थी उसमें उक्त भूखंडों से अपेक्षित राशि नहीं मिल सकी और यही कारण है कि अपीलकर्ताओं द्वारा बाद की नीलामी के लिए एक नया सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था। उक्त नीलामी आयोजित की गई थी और जैसा कि यहां पहले उल्लेख किया गया है, उक्त नीलामी से प्राप्त कीमत उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए प्रस्तावों की तुलना में बहुत अधिक थी। यह स्थिति होने और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि एक बाद की नीलामी आयोजित की गई और संपन्न हुई, उच्च न्यायालय के पास 8 जुलाई, 2004 को आयोजित नीलामी को वैध मानते हुए उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तावित दर पर वैकल्पिक भूखंडों के आवंटन का निर्देश देने का अधिकार नहीं था।

13. उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पटवालिया ने प्रस्तुत किया कि उनके ग्राहक दूसरी नीलामी में बोली लगाने

वालों द्वारा दी गई बड़ी हुई राशि का भुगतान करने के लिए तैयार थे और इसलिए, इसे देखते हुए, उच्च न्यायालय का निर्णय ऐसे संशोधन के साथ बरकरार रखा जाना चाहिए। हम श्री पटवालिया की इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं क्योंकि वर्तमान समय में, मामले में तीसरे पक्ष के हित बनाए गए हैं और दूसरी नीलामी में बोली लगाने वालों को रिट याचिकाओं में पक्षकार नहीं बनाया गया था।

14. आइए अब हम मामले के अन्य पहलू पर बात करते हैं जैसा कि यहां पहले उल्लेख किया गया है, सार्वजनिक सूचना में आरक्षित मूल्य नहीं दिखाया गया था और इसलिए, उत्तरदाताओं को आरक्षित मूल्य के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यहां तक कि अगर मान भी लिया जाए कि आरक्षित मूल्य सार्वजनिक सूचना में दिया जाना था, फिर भी, हमारा यह विचार है कि उच्च न्यायालय के लिए सबसे अच्छा रास्ता पूरी नीलामी को इस अदालत के फैसले *टाटा सेल्युलर* बनाम *भारत संघ* [उपर] के मद्देनजर रद्द कर दे न कि वैकल्पिक भूखंडों के आवंटन का निर्देश देकर अपनी राय रखे। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार को स्वीकार करना मुश्किल है कि चूंकि आरक्षित मूल्य प्रतिवादियों को ज्ञात नहीं था और वे उक्त नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाने वाले पाए गए, उन्होंने वैकल्पिक भूखंडों का आवंटन प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है और अपीलकर्ताओं को उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए उच्चतम प्रस्तावों को

अस्वीकार करने या नीलामी को ही रद्द करने का कोई अधिकार नहीं था। चूंकि पूरी नीलामी रद्द कर दी गई थी, इसलिए हमें कोई औचित्य नहीं मिला कि उच्च न्यायालय उसी नियम और शर्तों पर वैकल्पिक भूखंडों के आवंटन का आदेश कैसे पारित कर सकता है, जबकि रद्द करने के बाद, दूसरी नीलामी आयोजित की गई थी जिसमें प्राप्त कीमत उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए प्रस्तावों की तुलना में बहुत अधिक थी। इसके अलावा, हमें आरक्षित मूल्य का खुलासा न करने में कुछ भी अनुचित नहीं पाते। यह सामान्य ज्ञान है कि जब आरक्षित मूल्य का खुलासा किया जाता है, तो बोली लगाने वाले अक्सर समूह बनाते हैं और प्रकट मूल्य पर या उसके आसपास बोली लगाते हैं, हालांकि बाजार मूल्य काफी ज्यादा होता है। इसलिए, हम उच्च न्यायालय से सहमत नहीं हैं कि अपीलकर्ताओं ने निविदाएं आमंत्रित करते समय या नीलामी आयोजित करने के समय भी आरक्षित मूल्य का खुलासा न करके अनुचित तरीके से काम किया था।

15. इस स्वीकृत तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उत्तरदाताओं द्वारा अपीलकर्ताओं के साथ जमा की गई धनराशि उत्तरदाताओं को खाता प्राप्तकर्ता चेक द्वारा वापस कर दिया गया था, जिसे उनके द्वारा विधिवत भुनाया गया था और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बाद में, 20 दिसंबर, 2004 को दूसरी नीलामी आयोजित की गई थी। दूसरी नीलामी में उन्हीं भूखंडों के संबंध में जिन्हें 8 जुलाई, 2004 को नीलामी के लिए रखा

गया था और दूसरी नीलामी में कुछ अन्य पार्टियों ने अब उक्त भूखंडों में रुचि हासिल कर ली थी, उच्च न्यायालय के लिए खुला नहीं था कि वह अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए अपीलकर्ताओं को निर्देश करे कि उत्तरदाताओं को वैकल्पिक भूखंडों केवल इस आधार पर आवंटित किए कि 8 जुलाई, 2004 की नीलामी को बोर्ड के मुख्य प्रशासक द्वारा बिना कोई कारण बताए रद्द नहीं किया जा सकता है और इस आधार पर भी अपीलकर्ताओं द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस में आरक्षित मूल्य का खुलासा नहीं किया गया था।

16. मामले को देखते हुए, इसलिए, हम उच्च न्यायालय के निर्णय को कायम रखने में असमर्थ हैं और तदनुसार, उच्च न्यायालय का निर्णय रद्द किया जाने योग्य है।

17. उपरोक्त कारणों से, उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले को रद्द किया जाता है और अपील की अनुमति दी जाती है और रिट याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं। खर्च के संदर्भ में कोई आदेश नहीं होगा।

एस.के.एस.

अपीलें स्वीकृत।

चेतावनी: यह अनुवाद आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नगेंद्र मीना, (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण:- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सिमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणित होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।